

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

अन्त में मैं एक बार फिर सरदार स्वर्ण सिंह की प्रशंसा करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से इस स्थिति को सफलतापूर्वक संभाला।

प्रधान मंत्री तथा अगुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुतसे सदस्यों का भाषण सुना। मेरा विचार उनका भाषणों में कही गई सभी बातों का उत्तर देने कानहीं है। कुछ बातों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शेष बातों का उत्तर वैदेशिक-कार्य मंत्री स्वयं देंगे।

आरंभ में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब मैंने प्रधान मंत्री का पद संभाला था उस समय देश के सामने बड़ी बड़ी समस्याएँ थी जिनको सुलझाना था। मैं चाहता था कि भारत में शांति रहे और पड़ोसी राज्यों से हमारे संबंध अच्छे रहे। लंका के प्रधान मंत्री भारत एक वर्ष पहले यहाँ आये तथा कई वर्षों से जो समस्या हमारे सामने लटक रही थी उसको हमने संतोषजनक रीति से शांति से हल कर लिया। हमारी दिल्ली में उनसे बातचीत हुई तथा इस संबंध में एक समझौता हो गया तथा मुझे प्रसन्नता है कि लंका के नये प्रधान मंत्री उसको लागू करने के लिए बड़े उत्सुक हैं। मैं उसका बड़ा स्वागत करता हूँ। हमारे आपस में बड़े अच्छे संबंध हैं, मंत्रीपूर्ण संबंध हैं।

बर्मा में हमारे नागरिकों को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा तथा वे लोग बर्मा से लौट कर आ रहे हैं। मैंने अपने विदेश मंत्री श्री स्वर्ण सिंह से कहा है कि वह बर्मा जायें। वह वहाँ गए तथा उन्होंने बर्मा सरकार से बातचीत की। यद्यपि हमारी सभी समस्यायें उनके साथ हल नहीं हो पाई परन्तु कुछ सुधार अवश्य हुआ है। पहले हमारे नागरिकों को अपनी आस्तियाँ वहाँ पर छोड़नी पड़ती थी परन्तु अब कुछ स्थिति बदल गई है। बर्मा के प्रेसीडेंट जनरल ने विन भारत आए और उनसे हमारी बड़ी लाभदायक बातें हुईं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि अब हमारे संबंध उनसे बहुत अच्छे हो गए हैं।

मैं स्वयं काठमांडू गया था और स्पष्टतया कहना चाहता हूँ कि नेपाल और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं।

मैं बताना चाहता हूँ कि आरंभ में मेरी यही इच्छा थी पाकिस्तान से भी हमारे संबंध अच्छे हो जायें। मैं समझता हूँ कि यदि भारत और पाकिस्तान मित्रता से शांति से रहें तो बहुत अच्छा हो और इसी कारण मैं काहिरा से लौटते हुए कराची गया था। वहाँ पर प्रेसीडेंट अब्ब से मेरी बातचीत हुई। बातचीत से मुझे आशा बंधी थी कि संभवतया हमारी समस्यायें हल हो जायें। उनका विचार था कि, सीमाहों पर होने वाली मूठभेड़े बंद होनी चाहिए। मैंने भी उनको यही सुझाव दिया कि दोनों देशों के सैनिक अधिकारी मिल कर कोई ऐसा फार्मूला बना लें जिससे ये मूठभेड़े न हों। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि दोनों देशों के गृह-मंत्री मिलकर शरणार्थियों की समस्या हल कर लें। मैंने उनसे कहा कि मैं इन प्रस्तावों का स्वागत करता हूँ।

दिल्ली लौटने पर मैंने गृह-मंत्री सम्मेलन के बारे में प्रस्ताव भेजे परन्तु पाकिस्तान ने इस सम्मेलन का विलम्बन कर दिया। एक और तारीख निश्चित की गई जिसको भी पाकिस्तान ने नहीं माना। हमने तीसरी बार उन्हें लिखा। उनका उन्होंने उत्तर दिया कि "इस समय स्थिति ठीक नहीं है।" ऐसी बातें हुईं। मैं नहीं जानता था कि पाकिस्तान कुछ और तैयारियाँ कर रहा है। वह कुछ इलाके हड़पना चाहता है। पहले उसने कच्छ की रन पर हमला किया। हमने फिर भी मामले को शांति से निबटाना चाहा। हमने कच्छ की रन को खाली करना तथा उस पर चर्चा करना स्वोकार कर लिया। समझौता भी हो गया परन्तु फिर भी पाकिस्तान को संतोष नहीं हुआ और इसके विपरीत वह यह समझे कि इस कमजोर हैं और वह जबरन हम से कुछ भी करा सकते हैं। जम्मू तथा काश्मीर को पाकिस्तान में नह मिला सकते हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू तथा काश्मीर में घुमपैठिये भेजे। इन्होंने जम्मू तथा

काश्मीर में शांति तथा व्यवस्था को भंग करने का प्रयत्न किया तथा ऐसा प्रयत्न किया जिससे सुरक्षा परिषद तथा महासभा में ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जाये कि जम्मू तथा काश्मीर पर भारत का कोई नियंत्रण नहीं है। परन्तु उनको इसमें कोई सफलता नहीं मिली।

इसके बाद उन्होंने छम्ब के इलाके पर नियमित सेनाओं से हमला कर दिया। हमने इसके विरोध में बहुत कुछ हल्ला मचाया। परन्तु विश्व के किसी भी देश ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। सभी चुप रहे। परन्तु जैसे ही हमने लाहौर की ओर बढ़ना शुरू किया विदेशों में भारत के विरुद्ध वक्तव्य तथा लेख निकलने शुरू हो गये। ये हमारे साथ विदेशों ने अन्याय किया। उन्होंने हमारी बात तथा स्थिति को नहीं समझा।

अन्त में मामला सुरक्षा परिषद को भेजा गया। वहां पर इस पर विचार हुआ। हमने वहां भी यही कहा कि आक्रामक का पता लगाया जाये और अब समस्त विश्व को मालूम हो गया है कि किसने आक्रमण किया था। परन्तु सुरक्षा परिषदने अभी भी आक्रामक की घोषणा नहीं की है और इसी के फलस्वरूप दिन प्रतिदिन युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान को और प्रोत्साहन मिलता है कि वह ऐसे काम करे।

मैं नहीं जानता पाकिस्तानके क्या इरादे हैं। परन्तु एक ओर ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने लोगों को यह बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान अब भी लड़ रहा है। उन्होंने अपने लोगों में यह खबर फैला रखी है कि भारत हार गया है और पीछे भगा दिया है। परन्तु यह तथ्य है कि पाकिस्तान का एक बड़ा भाग हमारी सेना के कब्जे में है। मैंने संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव को लिखा है कि पहले युद्धविराम के प्रश्न का फैसला हो जाये फिर सेना पीछे हटाने के प्रश्न को लिया जाये। परन्तु सुरक्षा परिषद ने दोनों पर एक ही साथ विचार करने का फैसला किया है। हम इसके लिये तैयार हैं। परन्तु मैं दो बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक तो यह कि यदि पाकिस्तान युद्धविराम का उल्लंघन करता है तो हम उसको सहन नहीं करेंगे (अन्तर्बाधा)। दूसरे यह कि युद्धविराम के प्रभावशाली होने के पश्चात् हम किसी ऐसे समझौते पर राजी नहीं होंगे जिससे घुमपैठियों को फिर से हमारी सीमा उल्लंघन करने का अवसर मिले। राष्ट्रपति अयूब के साथ मेरी वार्ता के संबंध में भी कुछ बातें कही गई हैं। जैसा कि सभा जानती है यह मुझाव रूस सरकार ने बिल्कुल आरम्भ में दिया था। यद्यपि यह समय इन बातों के लिये मौजूद नहीं है फिर भी हमने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। मैं यह स्पष्ट कर देता हूं कि हम वहां पर काश्मीर के प्रश्न पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। यदि भारत और पाकिस्तान के संबंधों के प्रश्न को लिया जाये तो हम उसपर बातचीत करने के लिये तैयार हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और हम उसके साथ संबंध सुधारना चाहते हैं। परन्तु राष्ट्रपति अयूब और वहां के विदेश मंत्री यह समझते हैं कि समस्या का समाधान यह है कि काश्मीर पर बातचीत ही नहीं अपितु काश्मीर ही उनको मिल जाये। यह प्रस्ताव हमारे लिये स्वीकार करना बिल्कुल असम्भव है।

चीन के संबंध में मैं बहुत अधिक नहीं कहना चाहता। यह कहना कठिन है कि चीन और पाकिस्तान क्या तैयारी कर रहे हैं। परन्तु यदि चीन और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर हम पर हमला किया तो हमारे सामने कठिन स्थिति आ जायेगी। इसके लिये हमें तैयारी करना है और देश को औद्योगिक, आर्थिक और प्रतिरक्षा की दृष्टि से मजबूत बनाना है।

जहां तक गुटनिर्पक्षता की नीति का संबंध है मैं इसपर अधिक कहना नहीं चाहता। श्री मसानो ने पहली बार यह कहा है कि रूस के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध होने चाहिये। मुझे यह कहने के ज़रूरत नहीं कि कठिन समय में रूसने जो हमारी सहायता की हम उसको भुला नहीं सकते हैं।

भारत पाकिस्तान प्रश्न पर अमरीका से हमारे कुछ मतभेद हैं परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें अमरीका के साथ अच्छे संबंध नहीं रखने चाहिये। रूस और अमरीका ही दो बड़ी शक्तियां हैं जो संसार में शांति बनाये रख सकती हैं। ये दोनों देश शांतिपूर्वक ढंग से रहें तो संसार के सभी विकसित-सशोल देशों को सहायता मिलती रहेगी और संसार में शांति बनी रहेगी और लोग अच्छी तरह रहेंगे।

[श्री लालबहादुर शास्त्री]

यह सच है कि हमारे कुछ मित्रों ने स्पष्ट रूप से हमारा समर्थन किया है। जब कोई झगड़ा होता है तो अन्य देश यहाँ प्रयत्न करते रहे हैं कि उसका शांतिपूर्व ढंग से निपटारा हो जाये। वे अपने हृदय की बात को स्पष्ट नहीं करते हैं। अरब और मध्यपूर्व के कुछ देशों ने हमारा विरोध किया है। परन्तु फिर भी यह मानना पड़ेगा कि अरब शिखर सम्मेलन में किसी का भी पक्ष नहीं लिया गया।

उपनिवेशवाद के विरुद्ध हमारा रवैया गांधीजी के समय से ही रहा है। पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीका का अधिकांश देशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त की है। दक्षिण रोडेशिया के अल्पसंख्यक गोरे लोगों ने एक पक्षीय रूप से स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी है। हम बहुसंख्यकों के शासन में विश्वास करते हैं। हम रोडेशिया की गोरी सरकार को मान्यता नहीं देते। वहाँ के बहुसंख्यक अफ्रीकी लोगों को हमारा पूरा समर्थन प्राप्त है।

जहाँ तक मेरे अमरीका जाने का प्रश्न है मैंने पहले कभी इससे इनकार नहीं किया था। श्री पाटिल वहाँ पर निमन्त्रण का प्रबन्ध करने नहीं गये थे। निमन्त्रण तो पहले से ही था और जरूरत पड़ने पर फिर भी आ सकता था। और राष्ट्रपति जॉनसन की सुविधा को ख्याल में रख कर मुझे इसका निर्णय करना था कि कब जाया जाये। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के दिमाग से मैं यह भ्रम दूर कर देना चाहता हूँ कि कोई बात स्वीकार करने के लिये मुझ पर दबाव डाला जा सकता है।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 17 नवम्बर, 1965/26 कार्तिक, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the November 17, 1965/Kartika 26, 1887 (Saka).